ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 3, May 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 3, May 2023 |

भारत की विदेश नीति में मोदी का योगदान

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, Rajgarh Govt. College, Alwar, Rajasthan, India

सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा कार्यकाल शुरू किए हुए कुछ महीने हो चुके हैं और देश को उनकी विदेश नीति से भी काफी उम्मीदें हैं. मई 2014 में मोदी के पहली बार सत्ता में आने के बाद पांच साल की छोटी अवधि में विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ. मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर एकडमिक लिटरेचर तैयार हुआ है, वह पिछले किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ था. यहां तक कि सरकार के आलोचक भी भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव को स्वीकार करते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार ने बहुत कम समय में विदेश नीति पर स्पष्ट छाप छोड़ी है और उसने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं.इस साल दिल्ली में हुए 2019 रायसीना डायलॉग में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा था, "भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है. भारत आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना रहा है." अंतरराष्ट्रीय मंचों और एजेंसियों के ज़रिये दुनिया के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका बढ़ाने का वक्त आ गया है. गोखले ने इस पर जोर देते हुए कहा कि मल्टीलेटरल संस्थानों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी. विदेश सचिव ने साफ-साफ यह भी कहा कि भारत का भविष्य ख़ासतौर पर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जी20 और भारत-प्रशांत क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाता है. उनके इस बयान से इसका भी पता चला कि भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में क्या बदलाव आया है.गोखले के बयान को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है. मोदी के पहले कार्यकाल में सरकार विदेश नीति में धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निर्णायक बदलाव लाने में सफल रही थी. दिलचस्प बात यह है कि तब देश में कई एक्सपर्ट्स का इस पर ध्यान तक नहीं गया था. कुछ अहम बदलावों को लेकर भी आलोचक आशंकित थे. मोदी सरकार अभी भी भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता बदल रही है. विदेश नीति को लेकर उसका अंदाज़ ही नहीं, तौर-तरीका भी बदला है.

परिचय

गोखले के इस बयान से काफी पहले 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटिजिक स्टडीज में भारत, अमेरिका और चीन पर फुलर्टन लेक्चर दिया था. उन्होंने इसमें कहा था कि आज का भारत "दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है,[1] न कि बैलेंसिंग पावर." उन्होंने कहा था कि इसलिए भारत आज 'बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी' निभाने को तैयार है. जयशंकर के इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी की सोच की झलक थी. मोदी ने पहले कार्यकाल की शुरुआत के बाद अपने वरिष्ठ राजनयिकों से कहा था कि वे "भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में योगदान दें. देश को बैलेंसिंग पावर की भूमिका तक सीमित न रखा जाए."[2,3]

पिछले पांच सालों में मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है. उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा और योग्यता रखता है. भारत दुनिया में अपने लिए जो भूमिका चाहता है, उसे लेकर मोदी ने हिचक ख़त्म कर दी है. वह अपनी सभ्यता की 'सॉफ्ट पावर' की दावेदारी के लिए तैयार है. मोदी की इस पहल के बाद राजनयिक स्तर पर भारत का वैश्विक रसूख़ बढ़ाने की कोशिशें तेज़ हुईं.[4,5] इसके साथ योग और अध्यात्म जैसी सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों पर भी जोर दिया गया. यह बदलाव भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का ही प्रतीक नहीं है बल्कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए नियम तय करने की भूमिका हासिल करने की महत्वाकांक्षा भी है. वह खुद को दूसरे देशों के बनाए नियम पर चलने वाले राष्ट्र के रूप में सीमित नहीं रखना चाहता. पहले भारत विदेश नीति को लेकर किसी भी तरह के जोखिम से बचता आया था, लेकिन अब वह अपनी नई भूमिका हासिल करने के लिए रिस्क उठाने को भी तैयार है. दशकों से हम एक सतर्क विदेश नीति पर चलते आए थे, लेकिन 'ग्रेट पावर गेम' में भारत तेज़ी से कदम बढ़ाने और बड़ी भूमिका पाने के लिए तैयार है.[6,7]

पिछले पांच सालों में मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है. उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा और योग्यता रखता है. भारत दुनिया में अपने लिए जो भूमिका चाहता है, उसे लेकर मोदी ने हिचक ख़त्म कर दी है.[8.9]

जहां तक देश के सामरिक हितों का सवाल है, मोदी सरकार ने अपना अलग रास्ता बनाया है. वह दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाकर इसे मज़बूत कर रही है न कि इससे पीछे हट रही है. इस मामले में सरकार को ख़्याल रखना होगा कि यह पहल गुटनिरपेक्ष नीति का जुड़वां न साबित हो क्योंकि तब और आज की दुनिया में ज़मीन-आसमान का अंतर है. मिसाल के लिए, भारत कथित 'क्वॉड' से संपर्क बढ़ाने के साथ चीन के मामले में अपने लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है. इसके साथ, जब भारत, रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर रहा है तो वह ट्रंप सरकार के मामले में रणनीतिक स्वायत्तता को स्पष्ट कर रहा है. भारत ने यह रणनीति ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के स्तंभों को चुनौती देने के लिए अपनाई है.[10,11,12]

इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की विदेश नीति की समीक्षा की गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि अगले पांच वर्षों में देश की नई विदेश नीति को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और देश उनसे कैसे प्रभावित होगा. तीन खंड यानी हिस्सों वाली इस रिपोर्ट में पिछले पांच साल में देश की विदेश नीति की व्यापक समीक्षा की गई है. इसमें सरकार की उपलब्धियों के साथ उन चुनौतियों का भी ज़िक्र है, जिनका सामना देश के नीति निर्माताओं को करना पड़ रहा है.

पहले हिस्से में दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ भारत के रिश्ते का विश्लेषण किया गया है. कशिश परपियानी और मैंने भारत-अमेरिका के रिश्तों का विश्लेषण किया है. हमने पाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ रक्षा सौदों को लेकर कोई हिचक नहीं दिखाई है, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कारण दोनों देशों के रिश्तों में एक हाथ दे, एक हाथ ले पर ज़ोर बढ़ सकता है. वहीं, पिछले पांच सालों में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को मज़बूत बनाने की जो पहल की है, उसे संस्थागत रूप देने की ज़रूरत है. भारत और अमेरिका के नेचुरल अलायंस को मजबूत बनाने के लिए नौकरशाही, विधायी, सैन्य और यहां तक कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सभी स्तरों पर पहल करनी होगी.[13,14]

इसके बाद समीर सरन ने भारत के लिए चीन संबंधी चुनौती की पड़ताल की है. उनका कहना है, "यह एशिया की सदी है. इस सदी में बनने वाले मौकों और भारत-प्रशांत की सच्चाइयों के बीच तालमेल बनाना सरकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होगी." उनका सुझाव है कि "भारत को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए चीन के निवेश का इस्तेमाल करने के साथ एशिया के सामने विकास का एक वैकल्पिक मॉडल पेश करना चाहिए. इसके साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय कायदों और संस्थानों पर आधारित सुरक्षा का प्रस्ताव भी रखना चाहिए."

"यह एशिया की सदी है. इस सदी में बनने वाले मौकों और भारत-प्रशांत की सच्चाइयों के बीच तालमेल बनाना सरकार के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होगी." — समीर सरन

तीसरे चैप्टर में निवेदिता कपूर और नंदन उन्नीकृष्णन ने लिखा है कि भारत और रूस के बीच विदेशी नीति की प्राथमिकताओं पर मतभेद भविष्य में बने रह सकते हैं. इनमें सबसे बड़ा मुद्दा 'भारत-प्रशांत' का हो सकता है, जिस पर रूस अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर चुका है. दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति के बावजूद यह मसला आने वाले वर्षों में भारत-रूस की साझेदारी की राह में बाधा बन सकता है. निवेदिता और नंदन का कहना है कि बदलती हुई क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था में भारत और रूस दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश करेंगे.[15,16]

ब्रिटा पीटरसन ने भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के रिश्तों की पड़ताल की है. उनका कहना है कि पिछले पांच साल में भारत और ईयू के बीच आपसी रिश्तों को मज़बूत बनाने की पहल हुई है, लेकिन "चुनौती इस मोमेंटम को मज़बूत बनाए रखने को लेकर है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों के संबंधों में आने वाली जिन अड़चनों का ज़िक्र कई दस्तावेज़ों में हुआ है, उनकी अनदेखी न की जाए."

पांचवें अध्याय में भारत और जापान के संबंधों का विश्लेषण के वी केशवन ने किया है. वह कहते हैं कि "पहले दोनों देशों के रिश्ते आर्थिक सहयोग पर केंद्रित थे, लेकिन अब क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों को लेकर उनके बीच साझेदारी बढ़ रही है." लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर भारत और जापान की सोच एक जैसी है. साथ ही, दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक भी है.

दूसरे सेक्शन में भारत की विदेश नीति की कल्पना से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया है. कृति एम शाह ने इसमें दक्षिण एशिया की भूमिका की पड़ताल की है. उनका कहना है कि मोदी सरकार की नेबरहुड पॉलिसी में कनेक्टिविटी सुधारने, धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध कायम करने, विकास और मानवीय मदद करने पर जोर रहा है. इसे "क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए." मोदी सरकार जहां पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते मज़बूत बना रही है, वहीं 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी उसकी रणनीतिक जरूरत भी है.[17,18]

इसके बाद अनसुया बसु रे चौधरी और प्रेमेशा साहा ने भारत-प्रशांत में भारत की बढ़ती भूमिका का विश्लेषण किया है. भारत ने इस पहल के 'समावेशी चरित्र' पर ज़ोर देते हुए चीन और रूस जैसे देशों का भी स्वागत किया है. इस संदर्भ में भारत के लिए सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस क्षेत्र में भारत अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

आठवें अध्याय में अभिषेक मिश्रा ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों का ज़िक्र किया है. वो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी महादेश का केंद्र में आना महत्वपूर्ण है. उनका सुझाव है कि "भारत को उन मुद्दों की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें ध्यान में रखकर वह अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क और बढ़ा सकता है. इसके साथ उसे ऐसे उपाय भी करने होंगे, जिनसे भारत और अफ्रीकी देशों की साझेदारी सारी संभावित क्षमताओं का फायदा उठा सके."[19,20]

कबीर तनेजा हमें पश्चिम एशिया की तरफ ले जाते हैं, जहां भारत ने खाड़ी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की बुनियाद तैयार की है. पहले इस क्षेत्र में भारत के रिश्ते प्रवासी वर्कर्स और कच्चे तेल जैसे मुश्किल मुद्दों तक सीमित थे, लेकिन अब हमने इन बाधाओं को पार कर लिया है. कबीर कहते हैं कि "इस क्षेत्र के देश जानते हैं कि भारत किसी पर दबदबा नहीं बनाना चाहता. वह सबसे बराबरी का रिश्ता कायम करना चाहता है. इसके लिए वह पश्चिम एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी की पहल कर रहा है. इससे भारत को इस इलाके में रणनीतिक पकड़ बनाने में मदद मिल सकती है. बढ़ते आर्थिक रसूख़ से भी उसे इसमें मदद मिलेगी."

मध्य एशिया के मुत्तालिक भारत की विदेश नीति की पड़ताल ऐजाज वानी ने की है. वह कहते हैं कि "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने मध्य एशिया के साथ रिश्तों को अगले स्तर तक ले जाने की रणनीति अपनाई है. इस क्षेत्र के साथ भारत के सदियों पुराने सामाजिक-आर्थिक और पारंपरिक रिश्ते रहे हैं. भारत नई पहल के ज़रिये इसे दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है." उनका कहना है कि पहली बार भारत इस क्षेत्र को एक भौगोलिक इकाई के तौर पर देख रहा है. यह यूरेशिया क्षेत्र का हिस्सा है और इसलिए इसमें भारत की दिलचस्पी है.

केतन मेहता ने लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की पड़ताल की है. उनका कहना है कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क बढ़ाने में दिलचस्पी दिशाई है. भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता में यह क्षेत्र पहले कभी नहीं रहा, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भी लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी रिश्ते दिन-ब-दिन बेहतर हो रहे हैं. माना जा रहा है कि मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में लैटिन अमेरिका के लिए अलग से विदेश नीति के विजन पर काम कर सकते हैं. इस क्षेत्र में भारत की राजनयिक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार खर्च़ भी बढ़ा सकती है.[21,22]

तीसरे और अंतिम सेक्शन में वैश्विक मल्टीलेटरल ऑर्डर में भारत कहां है, इसका ज़िक्र किया गया है. अर्का बिस्वास ने दुनिया के परमाणु क्षमता से लैस देशों के साथ भारत के रिश्तों पर रोशनी डाली है. उनका कहना है कि 2014 से 2019 के बीच इन देशों के साथ भारत के संबंध मज़बूत हुए हैं, भले ही चीन ने अकेले एनएसजी में भारत की एंट्री रोक रखी है. असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में भारत ने नए समझौते किए हैं और मौजूदा समझौतों को लागू किया है. परमाणु संपन्न देशों के साथ नज़दीकियें बढ़ाने के लिए उसने राजनीतिक समर्थन भी जुटाया है.

"2014 से 2019 के बीच इन देशों के साथ भारत के संबंध मज़बूत हुए हैं, भले ही चीन ने अकेले एनएसजी में भारत की एंट्री रोक रखी है." — अर्का बिस्वास

दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों — संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण आर्शी तिर्की ने किया है. वह कहती हैं कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार कमोबेश पिछली सरकारों की राह पर ही चल रही है और वह उसे उस एजेंडे को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है. आर्शी का कहना है कि "भारतीय हितों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने

में तो सरकार सफल रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के स्तर पर इन्हें हासिल करने के लिए अभी बहुत काम करने होंगे." आखिरी चैप्टर में अपर्णा रॉय ने मोदी सरकार की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की चर्चा की है. वह कहती हैं कि 2017 के पेरिस समझौते से अमेरिका के पीछे हटने के बाद भारत इस मामले में दूसरे विकासशील देशों के लिए मिसाल बनकर उभरा है. भारत उनके सामने विकास संबंधी ज़रूतों के साथ पर्यावरण नीतियों के संतुलन का मानक पेश कर रहा है. अपर्णा का सुझाव है कि आने वाले वर्षों में भारत के सामने स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संभावित जोखिम और नीतिगत ज़रूरतों को लेकर एक नया ख़ाका पेश करने का मौका है.[23,24]

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले पांच साल में भारत की विदेश नीति बहुआयामी रही है. दुनिया के बारे में मोदी सरकार की सोच पुरानी बेड़ियों से आज़ाद है. इसमें विदेश मामलों में प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस बढ़ा है. इस रिपोर्ट में कई लेख़कों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की राह में कई चुनौतियां भी हैं. यह बात ख़ासतौर पर तब और अहम हो जाती है, जब सरकार को स्ट्रक्चरल, संस्थागत और विचारों के स्तर पर कई सवालों के जवाब तलाशने हैं. वैश्विक व्यवस्था में जिस तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, उसमें इन चुनौतियों को हल करना और मुश्किल होगा. कई देशों के साथ साझेदारी बनाने में उसकी राजनयिक क्षमताओं का इम्तेहान होगा. इसके साथ भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत को भी बनाए रखना होगा, तभी बड़े ग्लोबल पावर के उसके दावे की विश्वसनीयता बनी रहेगी. भारत अब ज़्यादा वैश्विक ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार है. ऐसे में ग्राउंड लेवल पर वह क्या कर पाता है, इसकी कहीं बारीक पड़ताल होगी. इसका मतलब यह भी है कि भारत अब सांस्थानिक कमज़ोरी को दूर करने में देरी गवारा नहीं कर सकता. इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की विदेशी नीति की समीक्षा ही नहीं है, इसमें यह भी बताया गया है कि भविष्य में देश की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए. इन विश्लेषणों के ज़रिये ओआरएफ का मकसद भारत की विदेश नीति के मौकों और चुनौतियों पर व्यापक बहस शुरू करना है ताकि देश एक बड़ी वैश्विक ताकत बनने की तरफ बढ़ सके.[25,26]

विचार-विमर्श

नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धान्त भी कहते हैं। २६ मई, २०१४ को सत्ता में आने के तुरन्त बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी । दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधारना मोदी की विदेश नीति के केन्द्र में है। इसके लिए उन्होने १०० दिन के अन्दर ही भूटान, नेपाल, जापान की यात्रा की। इसके बाद अमेरिका, म्यांमार, आस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा की।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, बहरीन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, यूएसए, यूके, मॉरीसस, मालदीव, यूएई दक्षिण कोरिया, चीन, ओमान, और श्रीलंका की यात्रा की है।[27,28]

अब माना जाने लगा है कि नरेन्द्र मोदी ने विश्व के बारे में भारत की सोच में आमूल परिवर्तन कर दिया है। [1]

मोदी सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन की प्रभावशीलता के बारे में बहुत कम सहमति है। कुछ लोगों का तर्क है कि मई 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से इसने भारत की विदेश नीति को बदल दिया है और देश के प्रमुख संबंधों और चुनौतियों से निपटने में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक सफल साबित हुआ है। दूसरों का तर्क है कि भारत की बुनियादी रणनीति अपरिवर्तित है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई दिल्ली की स्थिति आज कमजोर है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के संबंध में पहले के शासन की तुलना में। यह लेख इस बहस और विदेश नीति निर्माण में प्रधान मंत्री की स्वायत्तता की सीमा, विचारों और विचारधारा की भूमिका से संबंधित विशेष अंक में संबोधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों का परिचय है। कुछ भारतीय प्रधानमंत्रियों ने-पहले, जवाहरलाल नेहरू के स्पष्ट अपवाद के साथ- नरेंद्र मोदी के रूप में अपनी विदेश नीति के बारे में गहन और निरंतर बहस को प्रेरित किया है। [1] भाग में, यह मई 2014 के आम चुनाव (गांगुली 2017) में अपनी पहली भूस्खलन जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए वह और उनकी भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली सरकार द्वारा लाई गई ऊर्जा के कारण है [29,30]अपने पूर्ववर्ती, मनमोहन सिंह के विपरीत, मोदी एक बहुत ही उत्साही यात्री साबित हुए, कार्यालय में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई विदेशी यात्राओं की शुरुआत की, जैसा कि सिंह ने एक दशक में किया, हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला में भाग लिया, और साथ तालमेल स्थापित करने का लक्ष्य रखा। चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ दक्षिण एशिया में उनके समकक्ष। उनकी सरकार ने प्रमुख पहलों को भी नया रूप दिया- जैसे 'लुक ईस्ट', जिसे 'एक्ट ईस्ट' में बदल दिया गया- और दूसरों को लॉन्च किया, जिसमें भारत के पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना, ब्रांडेड 'नेबरहुड फर्स्ट'

शामिल है। इसने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ मध्य पूर्व से लेकर मध्य और दक्षिण एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले राज्यों के साथ अपने रक्षा और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का वादा किया। गौरतलब है,[31]

क्या मोदी और उनके मंत्रियों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त किया है या उन्हें उन नीतियों के साथ प्राप्त करेंगे जिन्हें उन्होंने लागू किया है, यह बेहद विवादित प्रश्न हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि मोदी सरकार ने क्रांति के साथ-साथ विदेश नीति को भी ऊर्जा दी है, राष्ट्रीय गौरव और दुनिया में देश की 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ावा दिया है, प्रमुख भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत किया है, और दुनिया में भारत की स्थिति को बहाल किया है, साथ ही आत्मविश्वास भी विदेशी निवेशकों की। 'मोदी सरकार की विदेश नीति परिवर्तनकारी रही है', एक अध्ययन का निष्कर्ष है, और मोदी ने 'खुद को' एक 'विश्व नेता' और 'नीति उद्यमी' दोनों के रूप में स्थापित किया है (ट्रेमब्ले और कपूर 2017: 218–219; 15) । [2]संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के उनके 'खुले आलिंगन' की दूरदर्शी और विवेकपूर्ण दोनों के रूप में प्रशंसा की गई है (जॉर्ज 2018 ; cf. पंत और जोशी 2017) और एक तेजी से मुखर चीन को निपुणता के रूप में संभालना (गोखले 2017 : 111) -140)। समानांतर में, कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी हमलों के लिए उनकी सरकार की प्रतिक्रिया - जिसमें भारतीय विशेष बलों द्वारा दंडात्मक छापे और पाकिस्तान में उचित हवाई हमले शामिल हैं - उनकी ताकत और इस्लामाबाद पर उनके कथित निवारक प्रभावों के लिए प्रशंसा की गई है (गोखले 2017) ।

अन्य कम प्रशंसात्मक हैं। कई विश्लेषकों का तर्क है कि मोदी और उनके मंत्रियों में जितना बदलाव पहली नज़र में देखा जा सकता था, उससे कम हुआ है। उनके लिए, भारतीय विदेश नीति की मूल रणनीति और समग्र 'प्रक्षेपवक्र', राजेश बसरूर ने इसे काफी हद तक 'अपरिवर्तित' (बसरूर 2017) रखा है। [3] कुछ लोगों का सुझाव है कि मोदी सरकार के विदेश नीति के बारे में सोचने या अभ्यास करने के लंबे समय से चले आ रहे तरीकों से टूटने के दावे असंबद्ध हैं (हॉल 2019)). कई लोग इसके प्रमुख संबंधों और चुनौतियों के प्रबंधन पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि 2014 के बाद से अमेरिका-भारत साझेदारी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है जितनी कि यह हो सकती है और यहां तक कि जब डोनाल्ड जे. ट्रम्प के विघटनकारी प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है, तब भी मोदी सरकार उन विफलताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करती है। (टेलिस 2018)। प्रशासन द्वारा चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को संभालने की और भी अधिक निरंतर आलोचना की गई है, भले ही उनके विभिन्न आलोचक समस्या के सटीक स्रोत पर असहमत हों (उदाहरण के लिए, बाजपेयी 2017; कर्नाड 2018 देखें) । मोदी पर भारत के नुकसान के लिए चीन के साथ अत्यधिक टकराव के लिए हमला किया गया है (झा 2017)), और साथ ही, अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग (थरूर 2018 : 450–455) के प्रति बहुत अधिक सम्मानपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई। आतंकवाद के कथित समर्थन को लेकर पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के उनकी सरकार के प्रयासों को अधिक समर्थन मिला है, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह संदेह बना हुआ है कि नियंत्रण रेखा पर उसके दंडात्मक छापे और कश्मीर में उसकी भारी-भरकम कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारत कमोबेश सुरक्षित है। (मजूमदार 2017)। [4] इसी तरह, व्यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने के मोदी के प्रयासों को बहुत मिश्रित मूल्यांकन प्राप्त हुआ है (राजगोपालन 2020)।[32]

परिणाम

इस विशेष अंक का उद्देश्य इन विवादों को सुलझाना नहीं है। बल्कि, यह मोदी सरकार के तहत भारत की विदेश नीति के अंतर्निहित चालकों की पड़ताल करता है और कुछ मान्यताओं का परीक्षण करता है जो इसके प्रदर्शन के निर्णयों को रेखांकित करती हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा, निश्चित रूप से, यह विचार है कि मोदी खुद एक परिवर्तनकारी नेता हैं जो घरेलू और विदेश नीति दोनों में बड़े बदलाव ला रहे हैं। [5] यह एक ऐसा विचार है जिसे वह और उनके समर्थक बढ़ावा देने के इच्छुक हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कठोर मूल्यांकन की मांग करता है। मुख्य कार्यकारी के भीतर नियंत्रण के केंद्रीकरण और क्षेत्र में संसदीय और सार्वजनिक हित दोनों के निम्न स्तर के कारण, अक्सर यह माना जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्रियों के पास अन्य लोकतांत्रिक नेताओं की तुलना में विदेश नीति निर्माण में असामान्य रूप से व्यापक अक्षांश है। [6]इसने साहित्य में विदेश नीति में बदलाव के साथ-साथ सफलताओं और असफलताओं की व्याख्या करने की एक निरंतर प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जो नेता सोचते हैं और करते हैं। और यह सुझाव देता है कि यदि मोदी के पास भारतीय विदेश नीति के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा है, तो वे इसे व्यवहार में लाने में सक्षम हो सकते हैं।[33,34]

हालांकि, हाल के अध्ययनों का तर्क है कि नेताओं पर इस ध्यान ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के व्यवहार के बारे में बार-बार भ्रामक स्पष्टीकरण दिया है, अन्य कारकों की कीमत पर क्या किया जाता है, यह निर्धारित करने की उनकी क्षमता पर अधिक बल दिया गया है, जैसे कि केंद्र सरकार के विभिन्न हिस्सों के बीच प्रतिस्पर्धा (हंसल देखें) एट अल 2017 फ्रेडरिक्स 2019). यह स्वयं प्रधान मंत्री, और उनके मंत्रियों और सलाहकारों, और उनके लिए काम करने वाले नौकरशाहों, नीति को आकार देने और लागू करने के साथ-साथ पार्टी के राजनीतिक मतभेदों से ध्यान हटाता है। दूसरों का तर्क है कि घरेलू नीति की तरह विदेश नीति में, नई दिल्ली और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच और केंद्र सरकार और देश के भीतर अन्य शक्तिशाली अभिनेताओं के बीच सौदेबाजी, जिसमें बड़े औद्योगिक समूह या कृषि हित शामिल हैं, मुख्य कार्यकारी को भी रोक सकते हैं। और इसके द्वारा किए जा सकने वाले विकल्पों को सीमित करें (देखें मट्टू और जैकब 2010)। इसके बाद, हम मोदी प्रशासन के मामले में, निश्चित क्षणों में, इन दोनों सीमाओं के सेट को संचालन में देख सकते हैं।

इस विशेष अंक में संबोधित धारणाओं का एक अन्य समूह विचारों और विचारधारा की भूमिकाओं से संबंधित है। मोदी सरकार ने भारतीय विदेश नीति की भाषा को बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जवाहरलाल नेहरू के प्रभुत्व वाले उत्तर औपनिवेशिक युग से विरासत में मिली शर्तों और अवधारणाओं को अलग कर दिया है, और स्वामी विवेकानंद के विचारों की हिंदू राष्ट्रवादी परंपरा से बड़े पैमाने पर तैयार किए गए नए लोगों को पेश किया है। और अरबिंदो घोष (हॉल 2019)। मोदी के समर्थकों का तर्क है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की यह पुनर्कल्पना या पुनर्खोज देश को दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए मुक्त कर रहा है और वैश्विक नेतृत्व के लिए नए अवसर खोल रहा है (चौलिया 2016)). लेकिन क्या ये प्रयास सफल रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है, और यह एक विवादास्पद बिंदु है कि क्या मोदी के तहत भारतीय विदेश नीति हिंदू राष्ट्रवादी सोच द्वारा निर्देशित है। कई विद्वानों का तर्क है कि यह विरासत में मिले विचारों द्वारा आकार लेना जारी रखता है, जो पहले के शोध के साथ फिट बैठता है जो समय के साथ विदेश नीति के बारे में भारत में अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण की स्थिरता की ओर इशारा करता है (गांगुली और अन्य 2017 देखें) । अन्य लोग मानते हैं कि मोदी सरकार का दृष्टिकोण, पहले के प्रशासनों की तरह, वृद्धिवाद और व्यावहारिकता द्वारा भी चिह्नित है (देखें बसरूर 2019 ; चटर्जी मिलर 2020)।[35,36]

धारणाओं का तीसरा समूह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एजेंसी और संरचना से संबंधित है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत के विकल्प विवश हैं क्योंकि इसकी भौतिक शक्ति अभी भी अपेक्षाकृत कम है और क्योंकि जिस संदर्भ में मोदी सरकार ने खुद को पाया है वह चुनौतीपूर्ण रहा है और बना हुआ है (पंत और रेज 2018 देखें ; टेलिस 2016)). वे एक परिणाम के रूप में तर्क देते हैं कि यहां तक कि एक नेता जो परिवर्तनकारी होने की इच्छा रखता है और विदेश नीति को एक नई भाषा में ढालने के लिए पर्याप्त परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के अलावा, जो 2014 में मोदी द्वारा किए गए वादे के अनुसार तेजी से नहीं सुधरी है, सबसे बड़ी बाहरी बाधा, ज़ाहिर है, चीन है। डेंग शियाओपिंग और उनके उत्तराधिकारियों के तहत पीपुल्स रिपब्लिक के तेजी से आर्थिक विकास को 1990 के दशक में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि यह एक संयुक्त राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौती बना रहा। चीन का विकास मॉडल भारत के कम गतिशील लेकिन यकीनन अधिक वैध दृष्टिकोण के लिए एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। इसका भारी वजन - जो अभी भी बढ़ रहा है - द्विपक्षीय संबंधों और भारत के तत्काल क्षेत्र दोनों को बदल रहा है, व्यापार और निवेश के तेजी से बदलते पैटर्न अपने पड़ोसियों को प्रभावित करते हैं। और इसका सैन्य आधुनिकीकरण, इसके अनिश्चित इरादों के साथ, एक अस्थिर सीमा पर संघर्ष की संभावना को बढ़ाता है।[37,38]

2013 में शी जिनपिंग के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के तुरंत बाद मोदी सरकार का सत्ता में आना शायद दुर्भाग्यपूर्ण था और 2017 से 2021 तक डोनाल्ड जे. ट्रम्प के राष्ट्रपति काल के दौरान सत्ता में रहना दोगुना दुर्भाग्यपूर्ण था। इसकी एजेंसी इन दो घटनाक्रमों द्वारा सीमित थी, जिसके कारण बीजिंग द्वारा कहीं अधिक मुखर व्यवहार और वाशिंगटन द्वारा अधिक सनकी व्यवहार, कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जोसेफ आर. बिडेन के उद्घाटन तक। चीन और अमेरिका दोनों के साथ तनाव और परेशानियों ने भारत के अपने निकटवर्ती पड़ोसियों, विशेष रूप से नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों को जटिल बना दिया है (इस विशेष अंक में जैकब देखें)। हालाँकि, उसी समय, जैसा कि इस अंक के कुछ लेख दिखाते हैं, बीजिंग और वाशिंगटन के बारे में साझा चिंताओं ने भी नई दिल्ली को ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित अन्य भागीदारों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए प्रेरित किया।

संक्षेप में, इस विशेष अंक का उद्देश्य मोदी सरकार की विदेश नीति की गहराई में उतरना है और यह समझाने की कोशिश करना है कि मई 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से इसके दृष्टिकोण ने ऐसा रूप क्यों ले लिया है। इसका उद्देश्य यह भी है 2020 की शुरुआत में

कोविड-19 महामारी की शुरुआत से एक धीमी अर्थव्यवस्था और एक तेजी से कठिन अंतरराष्ट्रीय माहौल के साथ संघर्ष करने वाले प्रशासन की सफलता और विफलता दोनों।

निष्कर्ष

इसके बाद के लेख मोदी सरकार द्वारा प्रमुख संबंधों के प्रबंधन या विदेश और सुरक्षा नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निपटने का पता लगाते हैं। पहले चार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों की जांच करते हैं। सुमित गांगुली का तर्क है कि मोदी का यूएस-भारत संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, सबसे पहले अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में उनकी किसी भी शिकायत को दूर करने में, और फिर बराक एच के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के प्रयासों में निवेश करने में .ओबामा और उसके बाद डोनाल्ड जे.ट्रम्प। वह यह भी मानते हैं कि मोदी सरकार का गुटनिरपेक्षता से हटना और रणनीतिक स्वायत्तता की खोज, भाजपा के भीतर अमेरिका-विरोधीवाद का तड़का लगाना, और ट्रम्प प्रशासन द्वारा मानवाधिकारों के मुद्दों की अवहेलना ने करीबी संबंधों की राह आसान कर दी, दोनों पक्षों के गलत कदमों और व्यापार को लेकर तनाव के बावजूद। हालांकि, उनका तर्क है कि संबंधों में सुधार का मुख्य कारण पूरे क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते मुखर व्यवहार के बारे में साझा चिंता थी।[30]

अपने योगदान में, मंजीत सिंह परदेसी मोदी के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हैं। वह स्मृति, स्थिति की चिंता, परस्पर विरोधी हितों और अनसुलझे मतभेदों के मिश्रण से आकार में द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता को देखता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि, अपने पूर्ववर्तियों की तरह, मोदी सरकार ने चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन, समायोजन और प्रतिस्पर्धा दोनों के संयोजन को नियोजित किया है। उनका तर्क है कि इसका विशेष मिश्रण बाहरी संतुलन पर भारी रहा है - मुख्य रूप से अमेरिका और भारत-प्रशांत क्षेत्र में अन्य 'समान विचारधारा वाले' राज्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करके - लेकिन चीन के आर्थिक विकास से उत्पन्न दबाव ने इसका प्रबंधन किया है द्विपक्षीय संबंध और भी कठिन

तीसरा लेख जापान के साथ भारत के बदलते संबंधों की ओर मुड़ता है। राजेश बसरूर और सुमिता नारायणन कुट्टी दोनों के बीच साझेदारी की उत्पत्ति और सार का पता लगाते हैं - जिसे अब 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' करार दिया गया है। वे भारत की लुक ईस्ट/एक्ट ईस्ट नीति और जापान के 'मुक्त और खुले भारत-प्रशांत' के दृष्टिकोण और दोनों के बीच औपचारिक संवाद तंत्र बनाने और रक्षा और सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों के अनुरूप हैं। वे भारत में जापानी सार्वजनिक और निजी निवेश की सीमा को भी रेखांकित करते हैं, जिसमें प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं, क्योंकि टोक्यो का उद्देश्य भारत के मध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है। वे द्विपक्षीय साझेदारी से परे बढ़ते लघुपक्षीय समन्वय और सहयोग का भी पता लगाते हैं,[31]

इयान हॉल का योगदान भारत की एक और रणनीतिक साझेदारी की पड़ताल करता है: ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका विकासशील, लेकिन विषम संबंध। उन्होंने नोट किया कि मोदी सरकार के चुनाव और छह महीने बाद ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा - 1986 के बाद से किसी भारतीय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा - ने कैनबरा में उम्मीद जगाई कि रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने और स्वतंत्र बातचीत करने में तेजी से प्रगति होगी। व्यापार अनुबंध। हालाँकि, उनका तर्क है कि चीन की महत्वाकांक्षाओं और मुखरता के बारे में दोनों राजधानियों में बढ़ती चिंताओं के बावजूद उन आशाओं को साकार नहीं किया गया। दोनों सेनाओं के बीच अधिक संवाद और अधिक सार्थक अभ्यासों के साथ, साझेदारी के सुरक्षा पक्ष में प्रगति स्थिर थी लेकिन असाधारण थी। लेकिन मुक्त व्यापार सौदे के लिए बातचीत रुक गई, और फिर नई दिल्ली क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक साझेदारी वार्ता प्रक्रिया से भी दूर चली गई, जिसका उद्देश्य पूर्वी एशिया में व्यापार की बाधाओं को कम करना है। भाग में, ये परेशानियाँ कैनबरा में नेतृत्व की अस्थिरता का एक उत्पाद थीं, लेकिन हॉल का तर्क है कि वे नई दिल्ली में संस्थागत कमियों का भी सुझाव देते हैं, क्योंकि मोदी सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति को ठोस परिवर्तन में अनुवाद करना कठिन लगा।

अगले दो लेख दो प्रमुख क्षेत्रों के राज्यों और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ भारत के संबंधों के मोदी सरकार के प्रबंधन का विश्लेषण करते हैं: दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व (या, जैसा कि नई दिल्ली पसंद करती है, पश्चिम एशिया)। हैप्पीमोन जैकब भारत के तत्काल क्षेत्र के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण का आकलन करता है। उनका तर्क है कि हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने कुछ प्रमुख राज्यों के साथ संबंधों को संचालित करने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी नोट किया कि मोदी और उनके मंत्रियों द्वारा शुरू में इस्तेमाल

की जाने वाली बयानबाजी के बावजूद, नई दिल्ली ने कभी-कभी अपने कुछ पड़ोसियों के साथ सीधी-सादी आक्रामक लाइन अपनाई है। वह घरेलू राजनीति और विदेश नीति के बीच संबंधों की भी पड़ताल करता है, एक ओर कश्मीर और भारत के नागरिकता कानूनों के बारे में, और केंद्र और भारत के सीमावर्ती राज्यों में चुनावी अनिवार्यताओं के बारे में।[32,33]

निकोलस ब्लेरेल पश्चिम एशिया के राज्यों के साथ भारत के बदलते रिश्तों की ओर मुड़ते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें यह स्पष्ट है कि मोदी और उनकी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। नई दिल्ली ने इज़राइल के साथ एक सुरक्षा साझेदारी को गहरा किया है - और इसे छाया से बाहर लाया है, कम से कम प्रधान मंत्री की यात्रा के साथ। मोदी ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों के साथ व्यक्तिगत कूटनीति में भी भारी निवेश किया है, निवेश फंड की मांग की है, क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के लिए बेहतर सुरक्षा, और तेल आपूर्ति तक पहुंच को कम किया है। कुल मिलाकर, मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ इनमें से कुछ राज्यों के संबंधों को ढीला करने के अपने लंबे समय से चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भी चिंतित रही है, क्योंकि यह इस्लामाबाद को अपने क्षेत्र से संचालित आतंकवादी समूहों के समर्थन पर अलग-थलग करना चाहती है।

अंतिम दो लेख संबंधों के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित हैं: भारत की उभरती विदेश आर्थिक नीति और वैश्विक परमाणु व्यवस्था में इसकी बदलती जगह। अमृता नार्लीकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करती हैं, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वह 'मेक इन इंडिया' और आत्मानबीर भारत अभियान जैसी योजनाओं की शुरुआत के बावजूद, जिस तरह से पहले के प्रशासन ने विदेश आर्थिक नीति को प्रबंधित किया है, उसके साथ निरंतरता का अवलोकन करती हैं।(आत्मनिर्भर भारत अभियान) 2019 के चुनाव के बाद से शुरू हुआ। नार्लीकर का तर्क है कि हालांकि मोदी सरकार कुछ लोगों की अपेक्षा से अधिक संरक्षणवादी रही है, यह दृष्टिकोण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर अनुकूल हो सकता है, जो 'हथियारयुक्त अन्योन्याश्रय' की विशेषता है।[34,35]

अंतिम पेपर में, राजेश राजगोपालन मोदी सरकार की परमाणु नीति की जांच करते हैं, जिसमें भारत के परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन, इसके परमाणु सिद्धांत और इसकी परमाणु कूटनीति शामिल है। उनका तर्क है कि यहां भी उम्मीद से कम परिवर्तन और अधिक निरंतरता रही है, भाजपा के इस आग्रह को देखते हुए कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत दृष्टिकोण अपना रही है और इसके संकेत हैं कि यह भारत को 'नो फर्स्ट यूज' से दूर ले जा सकता है। 1998 में हथियारों के परीक्षण के बाद से इसका सिद्धांत रहा है। उनका यह भी तर्क है कि, इसके चेहरे पर, ये नीति निरंतरताएं विषम हैं, क्योंकि भारत दो संभावित परमाणु विरोधियों- चीन और पाकिस्तान- का सामना कर रहा है, जो दोनों विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हैं। अपने शस्त्रागार और अपरंपरागत साधनों का उपयोग करते हुए, जिसमें सैनिकों और प्रॉक्सी द्वारा घुसपैठ शामिल है, नई दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए।[38]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. अभ्यंकर आरएम। भारतीय कूटनीति: सामरिक स्वायत्तता से परे। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2018. [गूगल स्कॉलर]
2. बाजपेयी, के. 2017. नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान और चीन नीति: मुखर द्विपक्षीय कूटनीति, सक्रिय गठबंधन कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय मामले 93 (1): 69-92।
3. बंद्योपाध्याय जे. भारत की विदेश नीति का निर्माण: निर्धारक, संस्थाएं, प्रक्रियाएं और व्यक्तित्व। बॉम्बे: एलाइड पब्लिशर्स; 1970. [गूगल स्कॉलर]
4. बसरूर आर. मोदी की विदेश नीति के मूल सिद्धांत: एक प्रक्षेपवक्र अपरिवर्तित। अंतरराष्ट्रीय मामले। 2017; 93 (1):7–26. डीओआई: 10.1093/ia/iiw006. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
5. बसरूर आर मोदी, हिंदुत्व और विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन परिप्रेक्ष्य। 2019; 20 (1):7-11। [गूगल स्कॉलर]
6. चाको पी. द राइट टर्न इन इंडिया: अधिनायकवाद, लोकलुभावनवाद और नवउदारीकरण। समकालीन एशिया का जर्नल। 2018; 48 (4):541–565। डीओआई: 10.1080/00472336.2018.1446546। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
7. चटर्जी मिलर एम. क्या नेता की विचारधारा विदेश नीति को प्रभावित करती है? नेहरूवाद बनाम मोदीतिवा। एशिया नीति। 2020; 27 (2):176–178। डीओआई: 10.1353/एएसपी.2020.0018। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]

8. चटर्जी मिलर एम, सुलिवन डी एस्ट्राडा के. 70 (विशेष अंक) अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का उदय। 2017; 93 (1):1-219। डीओआई: 10.1093/ia/iiw036. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
9. चौलिया एस मोदी सिद्धांत: भारत के प्रधान मंत्री की विदेश नीति। नई दिल्ली: ब्लूम्सबरी; 2016. [गूगल स्कॉलर]
10. छिब्बर पीके, वर्मा आर. आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी: द चेंजिंग पार्टी सिस्टम्स ऑफ इंडिया। न्यू योर्क, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस; 2018. [गूगल स्कॉलर]
11. फ्रेडरिक्स जी। गुटों से गुटों तक : विभिन्न पार्टी प्रणालियों में भारत की विदेश नीति भूमिकाएँ। इंडिया रिव्यू। 2019; 18 (2): 125–160। डीओआई: 10.1080/14736489.2019.1605120। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
12. गांगुली एस. क्या मोदी ने सच में भारत की विदेश नीति बदल दी है? वाशिंगटन त्रैमासिक। 2017; 40 (2):131-143। डीओआई: 10.1080/0163660X.2017.1328929। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
13. गांगुली एस, हेलविग टी, थॉम्पसन डब्ल्यूआर। भारतीय अभिजात वर्ग की विदेश नीति के दृष्टिकोण: भिन्नता, संरचना और आम भाजक। विदेश नीति विश्लेषण। 2017; 13 (2):416–438. [गूगल स्कॉलर]
14. जॉर्ज वीके। खुला आलिंगन: मोदी और ट्रम्प के युग में भारत-अमेरिका संबंध। नई दिल्ली: पेंगुइन; 2018. [गूगल स्कॉलर]
15. गोखले एन। सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे: पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत कुछ। नई दिल्ली: ब्लूम्सबरी; 2017. [गूगल स्कॉलर]
16. गुप्ता एस, मुलेन आरडी, बसरूर आर, हॉल I, ब्लेरेल एन, परदेसी एमएस, गांगुली एस। मोदी के तहत भारतीय विदेश नीति: एक नया ब्रांड या सिर्फ रीपैकेजिंग? अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन परिप्रेक्ष्य। 2019; 20 (1):1-45। डीओआई: 10.1093/आईएसपी/eky008. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
17. हॉल I. क्या भारतीय विदेश नीति में एक 'मोदी सिद्धांत' उभर रहा है? ऑस्ट्रेलियाई जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। 2015; 69 (5):247–252. डीओआई: 10.1080/10357718.2014.1000263। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
18. हॉल I. बहुसंरेखण और नरेंद्र मोदी के तहत भारतीय विदेश नीति। द राउंड टेबल: द कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। 2016; 105 (3):271–286। डीओआई: 10.1080/00358533.2016.1180760। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
19. हॉल I. मोदी और भारतीय विदेश नीति की पुनर्खोज। ब्रिस्टल: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस; 2019. [गूगल स्कॉलर]
20. हेंसल एम, खान आर, लेविलेंट एम, संपादक। भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत। लंदन और न्यूयॉर्क: रूटलेज; 2017. [गूगल स्कॉलर]
21. 2016 में जाफरलॉट सी. इंडिया: मोदी मध्यावधि का आकलन। एशियाई सर्वेक्षण। 2017; 57 (1):21–32. डीओआई: 10.1525/एएस.2017.57.1.21। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
22. झा पी.एस. मोदी के तहत चीन-भारत संबंध: आग से खेलना। चीन रिपोर्ट। 2017; 53 (2): 158-171। डीओआई: 10.1177/0009445517696630। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
23. मट्टू ए. चौंका देने वाला आगे: नरेंद्र मोदी और भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा। नई दिल्ली: पेंगुइन वाइकिंग; 2018. [गूगल स्कॉलर]
24. मट्टू ए, जैकब एच, संपादक। भारत की विदेश नीति को आकार देना: लोग, राजनीति और स्थान। नई दिल्ली: हर-आनंद; 2010. [गूगल स्कॉलर]
25. मजूमदार ए। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति: पुरानी बोतलों में पुरानी शराब का मामला। द राउंड टेबल: द कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। 2017; 106 (1):37-46. डीओआई: 10.1080/00358533.2016.1272957। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
26. मोहन सी.आर. मोदी की दुनिया: भारत के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स; 2015. [गूगल स्कॉलर]
27. ओग्डेन सी। टोन शिफ्ट: मोदी के तहत भारत की प्रमुख विदेश नीति का लक्ष्य। भारतीय राजनीति और नीति। 2018; 1 (1):2–23। डीओआई: 10.18278/inpp.1.1.2। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
28. पंत एचवी। भारतीय विदेश नीति: मोदी युग। नई दिल्ली: हर-आनंद; 2019. [गूगल स्कॉलर]
29. पंत एचवी, रेज ए. क्या भारत हिंद-प्रशांत के लिए तैयार है? वाशिंगटन त्रैमासिक। 2018; 41 (2):47–61। डीओआई: 10.1080/0163660X.2018.1485403। [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
30. पंत एचवी, जोशी वाई। मोदी के तहत भारत-अमेरिका संबंध: गले लगाने के लिए रणनीतिक तर्क। अंतरराष्ट्रीय मामले। 2017; 93 (1):133–146। डीओआई: 10.1093/ia/iiw028. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
31. प्लाजमैन जे, डेस्ट्राडी एस। पॉपुलिज्म एंड फॉरेन पॉलिसी: द केस ऑफ इंडिया। विदेश नीति विश्लेषण। 2019; 15 (2):283–301। डीओआई: 10.1093/एफपीए/ओरी010. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]

32. राजगोपालन आर. टालमटोल संतुलन: भारत की अव्यवहार्य भारत-प्रशांत रणनीति। अंतरराष्ट्रीय मामले। 2020; 96 (1):75–93. डीओआई: 10.1093/ia/iiz224. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]
33. सिंह एस, संपादक। मोदी और विश्व: (पुनः) भारतीय विदेश नीति का निर्माण। सिंगापुर: विश्व वैज्ञानिक; 2017. [गूगल स्कॉलर]
34. टेलिस ए जे। भारत एक अग्रणी शक्ति के रूप में। वाशिंगटन: कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस; 2016. [गूगल स्कॉलर]
35. टेलिस ए जे। नरेंद्र मोदी और अमेरिका-भारत संबंध। इन: देबरॉय बी, गांगुली ए, देसाई के, संपादक। न्यू इंडिया का निर्माण: मोदी सरकार के तहत परिवर्तन। नई दिल्ली: विजडम ट्री; 2018. पीपी। 525–535। [गूगल स्कॉलर]
36. थरूर एस. द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर: नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। नई दिल्ली: एलेफ; 2018. [गूगल स्कॉलर]
37. ट्रेमब्ले आरसी, कपूर ए. मोदी की विदेश नीति। नई दिल्ली: साधु; 2017. [गूगल स्कॉलर]
38. Wojczewski टी। लोकलुभावनवाद, हिंदू राष्ट्रवाद और भारत में विदेश नीति: 'द पीपल' इंटरनेशनल स्टडीज रिव्यू का प्रतिनिधित्व करने की राजनीति। 2020; 22 (3):396–422. डीओआई: 10.1093/आईएसआर/विज007. [CrossRef] [गूगल स्कॉलर]

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com